

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

36

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2546/PBR/2013 - विरुद्ध आदेश दिनांक  
15-4-2013 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल -  
प्रकरण क्रमांक 245/2010-11 अपील

इस्मायल खॉ बल्द ताज खॉ  
ग्राम भोरासा तहसील कुरवाई  
जिला विदिशा , मध्य प्रदेश  
विरुद्ध

---आवेदक

अशोक कुमार बल्द हरीशंकर  
निवासी मण्डी बामौरा तहसील  
बीना जिला विदिशा म०प्र०

---अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)

(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम०एस०ठाकुर)

आ दे श

(आज दिनांक ३ - ११ - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक  
245/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-13 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू  
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार कुरवाई को  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम भौरासा की भूमि नंबर 935/3 रकबा 1.349 है०





(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पूर्व में उसके नाम थी किन्तु अब किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि भूमि पर उसका संतरा, मौसमी का वगीचा लगा है । अनावेदक के यहाँ उसके द्वारा कर्ज लेकर भूमि गिरबी रखी थी किन्तु उसने नियत पर पूरी धनराशि लेने मना करते हुये अपना नामान्तरण करा लिया है इसलिये जाँच की जाकर उसके मौके पर कब्जे के कारण कब्जा दर्ज किया जाय । नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6-अ / 08-09 दर्ज किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 27-9-10 पारित किया तथा खसरे के कालम नंबर 12 में आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के समक्ष अपील क्रमांक 77 / 10-11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20-1-11 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया एवं अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 245 / 2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-13 अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये। लिखित तर्कों पर विचार करने के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का आवेदक एवं अनावेदक के बीच विक्रयनामा हुआ है और यह भी प्रमाणित है कि विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हुआ है अर्थात् वादग्रस्त भूमि अनावेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है। इसी भूमि पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6-अ / 08-09 में पारित आदेश दिनांक 27-9-10 से आवेदक का कब्जा दर्ज किया है। विचार किया जाना है कि क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का बेजा कब्जा दर्ज किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध





में अनुविभागीय अधिकारी ने चन्दन सिंह विरुद्ध कृपाल सिंह 2006 राजस्व निर्णय 104 एवं रामस्वरूप बनाम कलावती तथा अन्य 2007 राजस्व निर्णय 199 का अवलम्बन लेते हुये निर्णीत किया है कि धारा 115 सहपठित 116 के अधीन कब्जा लिखने के सम्बन्ध में किसी मामले का निराकरण नहीं किया जा सकता है एवं किसी व्यक्ति के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं लिखा जा सकता है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 245/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-13 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20-1-11 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है , जिसके कारण अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15-4-13 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 245/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

B  
Ma

  
(रामचंद्र सिंह)

सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर